रेडक्रॉस इकाइयों के निर्वाचन की हो नियमित व्यवस्था :पटेल

भोपाल(काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रदेश की जिला रेडक्रॉस समितियों के निर्वाचन कार्य की राजभवन में समीक्षा की। उन्होंने जिला इकाइयों जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है अथवा हो गया है। उनके निवार्चन की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए है।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, राज्य रेडक्रॉस समिति के जनरल सेक्रेटरी सहित राजभवन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस की सभी स्तर की इकाइयों के निर्वाचन की नियमित व्यवस्था हो। निर्वाचन कार्य समय पर हो। इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। प्रदेश की जिला इकाइयों का कार्यकाल अंतिम चरण में है अथवा पूरा हो गया है। उनके निर्वाचन का कैलेंडर जारी किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने रेडक्रॉस से संबंद्ध समितियों के निर्वाचन प्रक्रिया को भी शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों से राजभवन द्वारा रेडक्रॉस इकाइयों को दिए गए अनुदान के उपयोग की समीक्षा करने की अपेक्षा की है। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को उचित औषधियों की उपलब्धता में बाधा नहीं आए। उन्होंने इस की सतत मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया है।

ग्लोबल स्किल पार्क की सभी सीटें भरी जाएं: डॉ. यादव

प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में हो आईटीआई

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल स्किल पार्क की ब्रांड वैल्यू को स्थापित करते हुए यहाँ की सभी सीटें भरना सुनिश्चित किया जाएं। स्किल पार्क में संचालित सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों, उनकी उपयोगिता और रोजगारपरक क्षमता पर केंद्रित प्रचार-प्रसार अभियान का संचालन व्यापक स्तर पर किया जाए।

प्रदेश में विद्यमान उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर विकासखंड में आईटीआई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के समन्वय से गतिविधियां संचालित की जाएं। इससे युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। डॉ. यादव ने तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार विभाग की समीक्षा में यह निर्देश दिए। समत्व भवन में हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभाग में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के प्रति असंतोष व्यक्त किया। डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास और उनके लिए रोजगारपरक कार्यक्रमों के लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित कर परिणाममूलक गतिविधियां संचालित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मन और जापानी भाषाओं में दक्ष व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन भी भाषाओं में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना है, उनके प्रशिक्षण की प्रदेश में उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने तकनीकी रूप से दक्ष विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों को जोड़ते हुए युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। डॉ. यादव ने कहा कि इससे प्रदेश के उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध होंगे तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। बैठक में कौशल विकास नीति, रोजगार कार्यालयों और कौशल विकास के विलय, स्थानीय एवं परम्परागत पद्धतियों की पहचान के लिए आरंभ श्रुति कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के उन्नयन से बेहतर कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चितः मुख्यमंत्री

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के उन्नयन की स्वीकृति और अन्य विकास कार्यों की बहुमूल्य सौगात प्रदान करने पर केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की गति को और अधिक बढ़ाने के लिए रोड और हाईवे का विशाल नेटवर्क आकार ले रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन से क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना मध्यप्रदेश की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के शाहगढ़-बक्सवाहा-नरसिंहगढ़-दमोह से 63.50 किमी लंबाई के खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में अपग्रेड करने के लिए 531.84 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-34 उत्तराखंड के गंगोत्री धाम को मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर) पर लखनादौन से जोड़ता है। इन उन्नयन कार्यों में शाहगढ़-दमोह खंड के उन्नयन में 5 प्रमुख पुल, बक्सवाहा, भटेरा, नरसिंहगढ़ और पिपरिया चंपत में 4 बायपास और दमोह के निर्मित क्षेत्रों में सर्विस/स्लिप रोड (दोनों तरफ 1.3 किलोमीटर) शामिल हैं।

पार्थ योजना 9 स्थानों से होगी शुरू, 450 बच्चे होंगे लाभान्वित

भोपाल(काप्र)।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने टीटी नगर खेल स्टेडियम में एक मई से शुरू होने वाली पार्थ योजना की समीक्षा की। पार्थ योजना पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर और उज्जैन में शुरू की जा रही है। इस योजना के जरिये हर स्थान पर 50-50 बच्चों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।

श्री सारंग ने कहा कि योजना शुरू होने से पहले उन स्थानों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की जाये। साथ ही भोपाल से निर्धारित स्थानों पर आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने के लिये अधिकारियों को भेजा जाये, जो स्ट्रक्चर और इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का आकलन जिला खेल अधिकारी के साथ मिलकर करें। योजना में प्रशिक्षण पूर्व आकलन की एसओपी तैयार की जाये। इसके लिये कमेटी का भी गठन करें। हरेक प्रक्रिया की एसओपी हो। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। श्री सारंग ने बच्चों की सुविधा को देखते हुए समय निर्धारित करने को कहा। योजना के जरिये सप्ताह में 6 दिन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। उन्होंने रविवार के दिन प्रशिक्षणार्थी को स्वैच्छा से फिजिकल एक्टिविटी की छूट देने को कहा। श्री सारंग ने योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन, प्रशिक्षणार्थी पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु, प्रशिक्षण की अवधि, शुल्क, शारीरिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण समय, मानव संसाधन, प्रशिक्षक का मानदेय, वित्तीय प्रबंधन, आवश्यक सामग्री, किट, विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार आदि पर विस्तार से चर्चा की। श्री सारंग ने खेलो-बढ़ो अभियान के लिये स्कूलों का चयन कर कैलेण्डर बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने मास्टर ट्रेनर के रूप में गाइड की ट्रेनिंग कराने को भी कहा। साथ ही अभियान से संबंधित लिटरेचर और फिल्म प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिये, जिसके जरिये बच्चे खेलो-बढ़ो अभियान की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने इस दौरान बच्चों को नामी-गिरामी खिलाड़ियों से भी मिलवाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव और खेल संचालक राकेश गुप्ता उपस्थित थे।

भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा और त्याग का मार्ग दिखाया

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर कहा कि भगवान महावीर ने समाज को सत्य, अहिंसा व त्याग का मार्ग दिखाया है इनके विचार और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते है उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने कहा था कि हमें दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते है, उन्होंने समाज को जियो और जीने दो का मूलमंत्र दिया है। श्री देवड़ा ने भगवान महावीर जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब भगवान महावीर के आदर्शों को अपनाने और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें।

नौ संकल्प नई ऊर्जा का बनेंगे स्त्रोत : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए नौ संकल्पों से निश्चित ही नई ऊर्जा के स्त्रोत बनेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से नौ संकल्पों के पालन का आहवान किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस पर समारोह का शुभारंभ करते हुए नवकार मंत्र के महत्व को रेखांकित किया और मंत्र को एकीकृत ऊर्जा का प्रवाह बताया। प्रधानमंत्री ने सामूहिक नवकार मंत्र के जाप के बाद सभी से नौ संकल्प लेने का आग्रह किया।

ये हैं नौ संकल्पः जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता का मिशन, वोकल फॉर लोकल, देश दर्शन, नैचुरल फार्मिंग को अपनाना, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना, योग और खेल को जीवन में लाना और गरीबों की सहायता का संकल्प।

जल की बूंद-बूंद का संरक्षण करेंः तुलसी सिलावट

भोपाल(काप्र)।

जल संसाधन विभाग मंत्री तुलसी राम सिलावट ने बुधवार को जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत केरवा डैम के समीप श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी नागरिकों से जल की एक-एक बूंद को संरक्षित करने का आह्वान किया।

श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जल स्त्रोतों के संरक्षण, जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य व्यापक पैमाने पर किए जा रहे हैं। इस अभियान को सभी अपनी सक्रिय भागीदारी से सफल बनाएं।

केरवा डैम के समीप जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजित किए गए श्रमदान कार्यक्रम में विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक विष्णु खत्री, तीरथ मीणा, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद राजपूत, सरपंच श्रीमती मीरा तोमर, पर्यावरणविद् अभिलाष खांडेकर उपस्थित थे। श्री सिलावट ने अधिकारियों को जल स्त्रोतों के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के तालाबों पर हर प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल हटाने के भी सख्त निर्देश दिए। श्री सिलावट ने कहा कि जल संकट का समाधान जल गंगा संवर्धन अभियान में निहित है। उन्होंने झाबुआ जिले की प्रसिद्ध हलमा प्रथा से प्रेरणा लेते हुए सभी से अपने जीवन में कम से कम 1 घंटा श्रमदान करने का आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री शाह 13 अप्रैल को करेंगे राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शिरकत

भोपाल(काप्र)।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर श्री शाह सहकारिता विभाग की समीक्षा भी करेंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने इस परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम स्थल रवीन्द्र भवन में आयोजित होने वाले सम्मेलन की रूपरेखा तय की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल मौजूद थे। श्री सारंग ने निर्देश दिये कि कार्यक्रम स्थल पर विभागीय नवाचार संबंधी प्रदर्शनी लगाई जाये। उन्होंने बैठक के लिये बोर्ड रूम सहित हॉल और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा।

पीडीएस और गेहूँ उपार्जन की हुई समीक्षा

स्मार्ट पीडीएस एक मई से लागू करना प्रस्तावित : गोविंद राजपूत

भोपाल(काप्र)।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि स्मार्ट पीडीएस एक मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। श्री राजपूत ने पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भी सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य है।

अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने बुधवार को ई-केवायसी अभियान और न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ उपार्जन की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कर दोहरे एवं मृत हितग्राहियों के नाम सूची से विलोपित करवायें। ई-केवायसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप से भी ई-केवायसी किया जा सकता है। श्रीमती शमी ने इस कार्य में लगी टीम ग्राम/मोहल्ले में जाकर ई-केवायसी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी अभियान के दौरान राशन वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अमल का भी सहयोग लिया जाये।

एसीएस श्रीमती शमी ने गेहूँ उपार्जन की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्र पर बारदाना एवं हम्माल/तुलावटी की समुचित व्यवस्था करें। स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्रों में तौलकांटों की संख्या बढ़ाई जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन किसानों द्वारा स्लॉट बुक कर लिया गया है, उनसे उपज विक्रय के लिये सम्पर्क करें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड के गेहूँ का ही उपार्जन करें। उपार्जित गेहूँ के परिवहन पर विशेष ध्यान दें। असामयिक वर्षा से उपार्जित गेहूँ की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसानों को बैठने के लिये छायादार स्थल, पेयजल एवं जनसुविधा की व्यवस्था करें। बैठक में आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री अनुराग वर्मा, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री को खून से पोस्टकार्ड लिखेंगे अंशकालीन कर्मचारी

भोपाल (काप्र)।

प्रदेश के अंशकालिक कर्मचारी 1 मई मजदूर दिवस के दिन भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में मुख्यमंत्री के नाम खून से पोस्टकार्ड लिखेंगे।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि पिछले 20 सालों से अंशकालीन कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि नहीं की गई है और ना ही उन्हें कोई भत्तों का लाभ दिया गया है। अंशकालीन कर्मचारियों को 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मात्र 5 हजार वेतन भुगतान किया जा रहा है। वेतन भुगतान भी 6 माह बाद किया जाता है। समय पर वेतन भुगतान कभी नहीं किया जाता है। अंशकालीन कर्मचारी की वरिष्ठ सूची भी नहीं बनाई गई है। अंशकालीन कर्मचारियों को बीमा सुविधा पीएफ सुविधा का लाभ भी नहीं दिया गया है। अंशकालीन कर्मचारियों द्वारा बार-बार मांग करने के बादजूद भी कलेक्टर दर का वेतन और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का दर्जा राज्य सरकार ने नहीं दिया है। इस कारण प्रदेश के 55 हजार अंशकालीन कर्मचारी में असंतोष व्याप्त है।

स्पेशल खबर *एमईएस बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ऑल इंडिया काउंसिल मीट-2025 में उप मुख्यमंत्री हुए शामिल...*

भारत के महानिर्माण में प्रत्येक नागरिक, संस्था और संगठन की भूमिका महत्वपूर्णः शुक्ल

भोपाल(काप्र)।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में वैश्विक क्षितिज पर उभर रहा है। यह भारत का महानिर्माण काल है, जिसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री शुक्ल सफल रिट्रीट भोपाल में एमईएस बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ऑल इंडिया काउंसिल मीट-2025 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। श्री शुक्ल ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को आशा और संभावनाओं की दृष्टि से देख रही है। भारत वह राष्ट्र है जो विश्व में शांति स्थापित करने की सामर्थ्य रखता है। आज का भारत अपने निर्णय अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं, बल्कि वैश्विक हित में लेता है। हमारी सेनाएं पूरी मजबूती के साथ खड़ी हैं। अब वह समय नहीं जब हम ज़मीन पर विजय के बाद टेबल पर हार जायें, अब हम दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के साथ जुड़कर कार्य करना गौरव और राष्ट्रसेवा का अवसर है। एमईएस बिल्डर्स एसोसिएशन के सदस्य सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। सैन्य क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता, अनुशासन और प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और एसोसिएशन इन सभी मानकों पर खरा उतर रहा है।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। भविष्य में हथियार भी भारतीय होंगे उन्हें चलाने वाले भी स्वदेशी होंगे। एमईएस बिल्डर्स एसोसिएशन के सदस्य भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत माता की सेवा कर रहे हैं, यह अत्यंत गर्व की बात है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 80 जिलों से आए एसोसिएशन के पदाधिकारी, बिल्डर्स, सैन्य क्षेत्र से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।